(d) whether Government propose to recover the whole money from Shri Sanjay Gandhi?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). Yes, Sir. In connection with Lok Sabha Unstarred Questions No. 68, No. 528 and No. 3444 answered on 6-4-1977, 15-6-1977 and 13-7-1977 respectively the State Governments were asked to furnish details regarding the visits of Shri Sanjay Gandhi to the States. The information collected has been laid on the Table of the House in reply to the above Questions.

(d) This is a matter for the State Governments to consider.

राजस्थान के भागों के विकास के लिए धनराशि का नियतन

4102. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत सरकार ने हाल में राजस्थान के कुछ भागों के विकास के लिए कुछ धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो उस धनराशि के खर्च के लिए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने 1977-78 के दौरान राज्य की आदिवासी उप-योजना के बारे में राजस्थान को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 2.60 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। 58 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार को पहले ही दे दी गई है। धनराशि आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के विकास में राज्य के प्रयास में सहायता के लिए है, जो 6 83 करोड़ रुपए होगी। यह राशि निम्नलिखित कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी :—

(1) कृषि

(2) सहकारिता

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण

(4) उद्योग

(5) सड़क तथा पुल

(6) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं।

बेतूल का विकास

4103. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक दृष्टि से क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने अथवा कम करने के लिये सरकार का विचार नये उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में बेतूल को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी जो पिछड़ा हुआ और आदिवासी क्षेत्र है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख). संतुलित क्षेत्रीय विकास सरकार की स्वीकृत राष्ट्रीय नीति है। सरकार ने तकनीकी आर्थिक बातों को ध्यान में रख कर पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की है साथ ही ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिये जाते हैं। मध्य प्रदेश का बेतूल जिला पहले से ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने के लिए स्वीकृत जिलों में से है किन्तु यह निवेश पूंजी राज्य सहायता पाने का पात्र नहीं है।

Reduction in Overhead Cost by CIL

4104. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Coal India Ltd. has effected a reduction in overhead expenses to the tune of Rs. 100 crores

per year (news report in *Statesman*, Calcutta Edition of 28th May, 1977);

(b) if so, the percentage this reduction constitute of the total overhead cost, items of expenses included in overhead cost and since when this total overhead cost is being changed;

(c) whether the extent of overhead expenses charged is not to excessive, if so, why is it being allowed and with what view; and the factors which persuaded the authority to declare this huge reduction immediately after the formation of Janata Government; and

(d) whether it was not possible to effect this reduction earlier although such scope was clearly stressed to the then Minister of Energy as back as March, 1975 by a very senior and experienced mining engineer who has been kept out of service by Coal India Ltd. and brought to a state of virtual starvation?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The rapid increase in coal demand during the period 1973—76, however, enabled the coal industry to better utilise men and machinery and this got reflected in the part containment of the impact of wage increase and of inflation.

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों के विकास के लिए बी० पी० पटेल आयोग

4105. **श्री उग्रसेन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों—गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर के लिए श्री बी० पी० पटेल आयोग द्वारा सिफारिश की गई विशेष परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता दी है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों में विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए 1962 में श्री बी० पी० पटेल की अध्यक्षता में योजना आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त अध्ययन दल गठित किया गया था। दल का विचार था कि कालांतर में निम्नलिखित औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की संभावना हो सकती है :—

1. निजी क्षेत्र

(1) 8 चीनी के कारखाने—चारों जिलों में से प्रत्येक में दो-दो।

(2) 2 शराब के कारखाने।

(3) 4 कागज के कारखाने।

(4) 2 लकड़ी के फट्टे बनाने के कारखाने।

(5) 'पावर अलकोहल' पर आधारित रासायनिक उद्योग।

(6) दो सूती वस्त्र बनाने के कारखाने—एक गाजीपुर में और दूसरा आजमगढ़ में।

(7) देवरिया में बड़े पैमाने का निर्माण संयंत्र।

2. सरकारी क्षेत्र

(1) मशीन टूल्स इकाई।

(2) मशीन टूल्स सहायक उपकरण इकाई।

(3) टूल बरमा इकाई।

(4) छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाली इकाई।

(5) एक या दो आयुध कारखाने।